

पाठ 3 - नियोजित विकास की राजनीति

अध्याय-समीक्षा

- इस्पात की विश्वव्यापी माँग बढ़ी तो निवेश के निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा उड़ीसा में लौह-अयस्क का विशाल भंडार था और अभी इसका दोहन बाकी थे। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह-अयस्क की इस अप्रत्याशित माँग को भुनाना चाहा। उसने अन्तराष्ट्रीय इस्पात-निर्माताओं के साथ सहमति -पत्र हस्ताक्षर किए। सरकार सोच रही थी कि इससे राज्य में जरूरी पूँजी- निवेश भी हो जाएगी और रोजगार के अवसर भी संख्या में सामने आएँगे।
- इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक-समूह के हितों को दूसरे सामाजिक -समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। साथ ही मौजूदा पीढ़ी के हितों और आने वाली पीढ़ी के हितों को भी लाभ हानी की तुलना पर मापना पड़ता है। किसी भी लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लोए जाने चाहिए या कम-से-कम इन फैसलों पर विशेषज्ञ की स्वीकृति की मुहर जरूर चाहिए खनना, और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञों की राय जाना महत्वपूर्ण है ,
- आजादी के बाद अपने देश में ऐसे कई फैसले लिए गए। इनमें से कोई भी बाकी फैसलों से मुँह फेरकर नहीं जा सकता था। सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या यो कहे कि एक विजन से बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे भारत के विकास का अर्थ आर्थिक स्त्रिदी और आर्थिक न्याय दोहा इस बात पर भी सहमती थी कि इस मामले को व्यवस्था उद्योगपति किया जाता गई है
- अकसर इन टकरावों के पीछे विकास की धरनाओं का हाथ होता है। उड़ीसा के उदाहरण से हमें पता चलता है इतना ख देने भर से बात भी से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग-अलग होते हैं ?
- आजादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर खूब बहसे हुई। उस वक्त लोग -बाग वीकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे का पैमाना पश्चिमी मुल्क है। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं।
- आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो माडल थे। पहला उदारवादी -पूँजीवादी मांडल था। यूरोप के अधिकतर हिन्सो और संयुक्त राज्य अमरीका में यही मांडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मांडल था। इसे सोवियत संघ ने अपनाया था।
- योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में, भारत सरकार ने एक सीधे-सादे प्रस्ताव के जरिए की। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूर करे।
- नीति - निर्देशिक तत्वों के अंतर्गत यह भात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसे समाज -रचना को बनाते - बचाते हुएलोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहाँ राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक होता है। (क) स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर-बराबर अधिकार हो (ख)समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियन्त्रण को इस तरह बंटा जाएगा कि उससे सर्वसामान्य की भलाई हो : और (ग) अर्थव्यवस्था का संचलन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएँ और जनसामान्य की भलाई बाधित हो
- मतभेदों के बावजूद एक बिन्दु पर सभी सहमत थे विकास का काम निजी हाथों में नहीं सोफा जा सकता और साकार के लिए जरूरी है कि वह विकास का एक खाका अथवा योजना तैयार करे। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 1950 के दशक में पूरे पूरे विश्व में जनसमर्थन मिला था।
- जापान और जर्मनी ने योद्ध की विभीषिक झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी और सोवियत संघ ने 1930 तथा 1940 के दशक में भारी कठिनाई के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी।
- 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी किया गया। नियोजन को लेकर देश में जो गहमागहमी पैदा हुई थी वह 1956 से चालू दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ अपने चरम पर पहुँच गई। 1961 की तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय तक यह माहौल जारी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से चालू होना थी।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) की किशिश देश को गरीबी के मकडजाल से निकलने की थी। योजना को तैयारी करने में जुटे विशेषज्ञों में एक के.एन. राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले दो दशक तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए।
- प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत में इससे कही ज्यादा बचत की उम्मीद की गई थी। बाद के दिनों में यानी 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक के शुरुआत सालों तक बचत की मात्रा में लगातार कमी आई।

- दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पी.सी. महलनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों की एक टोली ने यह योजना तैयार की थी। ज्यादा संसाधन लगाए जाने चाहिए। कियो का मानता था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में करीबी के विकास की रणनीति का अभाव था।
- 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा में एक नया मोड़ आती है। पाँचवें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि नेहरू की मीरिती के बाद कांग्रेस -प्रणाली संकट से घिरने लगी। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों पर और बाधाएं आयद हुई। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सरकार ने गरीबी की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की।
- 1950 से 1980 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3-3.5 प्रतिशत की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योगों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा। जनता का भरोसा टूटता देखा नीति-निर्माताओं ने 1980 के दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया।

अभियास

Q1. बांम्बे प्लान' के बारे में निम्नलिखित में कौन-सा बयान सही नहीं है।

- (क) यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लू-प्रिंट था।
- (ख) इसमें उद्योगों के उपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था।
- (ग) इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी।
- (घ) इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था।

Q2. भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन-सा विचार शामिल नहीं था ?

(क) नियोजन	(ख) उदारीकरण
(ग) सहकारी खेती	(घ) आत्मनिर्भरता

Q3. भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार - ग्रहण किया गया था :

(क) बांम्बे प्लान से	(ख) सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से
(ग) समाज के बारे में गांधीवादी विचार से	(घ) किसान संगठनों की मांगों से

(क) सिर्फ ख और घ	(ख) सिर्फ क और ख
(ग) सिर्फ घ और ग	(घ) उपर्युक्त सभी

Q4. निम्नलिखित का मेल करे :

(क) चरण सिंह	(i) औद्योगीकरण
(ख) पी.सी. महालनोबिस	(ii) जोनिंग
(ग) बिहार का अकाल	(iii) किसान
(घ) वर्गीज कूरियन	(iv) सहकारी डेयरी

Q5. आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे ? क्या इन मतभेदों को सुलझा लिया गया ?

Q6. पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था ? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी ?

Q7. हरित क्रांति क्या थी ? हरित क्रांति के दो सकारात्मक और दो नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें ।

Q8. दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था इस विवाद में क्या-क्या तर्क दिए गए थे ।

Q9. अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति - निर्माताओं ने गलती की । अगर शुरूआत से ही निजी क्षेत्र को खुला छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज्यादा बेतर तरीके से होता । इस विचार के पक्ष विचार के पक्ष या मैं अपने तर्क दीजिए ।

Q10. निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें :

आजादी के बाद के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ पनपीं एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कार्यकारिणी ने राज्य के स्वामित्व का समाजवादी सिद्धांत अपनाया ,उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण

क्षेत्रों का नियंत्रण और नियमन किया । दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय की राष्ट्रीय सरकार ने निजी निवेश के लिए उदार आर्थिक नीतियाँ अपनाई और उसके बढ़ावे के लिए विशेष कदम उठाए । ऐसे उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की अकेली कसौटी पर जायज ठहराया गया ।

(क) यहाँ लेखक किस अन्तर्विरोध की चर्चा कर रहा है ? ऐसे अन्तर्विरोध के राजनीतिक परिणामों क्या होंगे ?

(ख) अगर लेखक की बात सही है सही है तो फिर बताएं कि कांग्रेस इस नीति पर क्यों चल रही थी?

(ग) क्या कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय नेत्रित्व और इसके प्रांतीय नेताओं के बीच भी कोई अंतर्विरोध था ?